बजट भाषण

2024—2025

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि, आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का 10वां बजट दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत हो रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर प्यार, आशीर्वाद और भरोसा बनाकर रखा है।

2. मैं व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज, मैं सिर्फ 2024-25 का बजट प्रस्तुत नहीं कर रही, पिछले 10 साल की दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर, इस सदन के सामने रख रही हूँ।

3. 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे, मैं देखती थी कि, दिल्ली के लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा था। वो चुनाव में वोट डालने जाते जरूर थे, लेकिन उनके मन में यह सवाल रहता था कि, उनके वोट से क्या ही होगा। उन्हें लगता था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पर एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। उसकी जिंदगी में हमेशा दुख, परेशानी, संघर्ष बना ही रहता था। जब पहली तारीख को एक आम इंसान के हाथ में तनख्वाह आती थी और वह उसे अपने परिवार को देता तो सभी को ये चिंता होती थी कि, इतने पैसे से महीना कैसे निकलेगा। 25 तारीख आते-आते जब ये पैसे ख़त्म हो जाते थे तो हर गृहिणी को चिंता सताती थी कि, महीने के आखिरी 5 दिन कैसे बीतेंगे।

4. एक आम परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता, तो उसके इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था, अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते, अपना मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करता था। अपना पेट काटकर बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था। इसके बावजूद पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती थी। इन्ही सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सरकारों पर से ही नहीं बल्कि अपने वोट से भी भरोसा उठ गया था।

5. ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी उम्मीद की किरण बनकर आए। दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई पर भरोसा किया, उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर अपना मुख्यमंत्री बनाया।

6. हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित है, इसलिए हमनें दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरित्र मानस में भी लिखा है कि -

राम राज नभ गेस सुनु, सच राचर जग माहिं|

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहु हि नाहिं||

7. अर्थात- "श्री राम के राज्य में जड़, चेतन सारे जगत् में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुःख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। हम 9 सालों से दिल्ली के हर इन्सान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हर परिवार को सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास कर रहे है।

8. अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने के इस सफ़र में हमें लम्बी दूरी तय करनी है। लेकिन आज, मैं केजरीवाल सरकार का दसवां बजट पेश करते हुए ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि, 10 सालों में दिल्ली के आम लोगों की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 2014-15 से 2024-25 तक का ये सफ़र, दिल्ली और दिल्लीवालों के लिए एक बदलाव का सफ़र रहा है| चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर दो गुणा बढ़ी हुई प्रतिव्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हो या महिलाओं को मिली टैंकरों के लड़ाई झगडे से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज| दिल्लीवालों ने 2014-15 से 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफ़र तय किया है| जब हम दिल्ली के लोगों के बीच जाते है तो हमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की मुस्कान से अपना रिपोर्ट कार्ड तो रोज मिलता है, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने पिछले 10 साल में रामराज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए क़दमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी|

9. जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था| आज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी रामलला जी के अयोध्या जैसी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे है। दिल्ली में राम राज्य के इस सफ़र में, एक महत्वपूर्ण द्योतक है, दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का GSDP ₹ 4 लाख 95 हजार करोड़ था, और आज दस साल के अंदर ,अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग ढाई गुणा बढ़कर, वर्तमान क़ीमतों पर 11 लाख 08 हजार करोड़ हो गया है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 47 हजार रूपये थी, और 2023-24 में वर्तमान क़ीमतों पर 4 लाख 62 हजार रूपये है; जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुणा ज़्यादा है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है।

10. पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्लीवासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही साथ दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30 हज़ार 940 करोड़ रुपये था, और वित्त वर्ष 2024-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76 हज़ार करोड़ रूपये का बजट इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूँ। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी और राज्य के बजट में हुई होगी। वर्ष 2014-15 में 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15 हज़ार 89 करोड़ रुपये है, जो 2014-15 के दोगुना से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76 हज़ार करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें एक पैसा नहीं आने वाला।

11. अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते है कि रामराज्य में कोई भी गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध था| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ये मानते है कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना|

शिक्षा

12. दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविन्द केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया। और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए है|

13. मुझे याद है कि, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में सरकारी स्कूलों का क्या हाल था। आप स्कूल के अंदर जाते तो घुसते ही सबसे पहले गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी, पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियाँ टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, न क्लासरूम में डेस्क होते थे, न ब्लैकबोर्ड, न ही टीचर। जर्जर-टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अँधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था, मानों बच्चों की शिक्षा कहीं गुम हो गई हो| कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को दिल पर पत्थर रख कर मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं अपने बच्चो को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाता।

14. ऐसा लगता था कि एक तीन साल के बच्चे के हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो अमीर घर में पैदा हुआ और उसके माता-पिता बड़े प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे पाते तो उसका भविष्य उज्जवल होना तय था| वो अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और कॉलेज से पास आउट होने के बाद एक अच्छे पैकेज की नौकरी लेकर निकलता| अगर गरीब घर में

पैदा होता तो उसके माता-पिता उसे टूटे-फूटे सरकारी स्कूल मे भेजते, और शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाता| अगर पढ़ाई पूरी कर भी ली, तो सरकारी स्कूल में शिक्षा के ख़राब स्तर की वजह से उसे कही मैकेनिक का, छोटी सी दुकान में हेल्पर का, या किसी के घर में काम करना पड़ता था| ऐसे में अमीर का बच्चा अमीर और गरीब के बच्चे का गरीब बनना तय था| ये तो राम राज्य के सपने से बिलकुल विपरीत परिस्थिति थी।

15. लेकिन दिल्ली के इस दस साल की बदलती हुई तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है| केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया| ये सब कुछ बदल दिया| आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़कर किसी भी उंचाई को छू सकता है| जैसे हमारे स्कूलों के इन बच्चों ने किया है-

- अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के रोहिणी, सेक्टर 23 के स्कूल से पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी से फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करने के लिए शिम्पी अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से उसने IIT-JEE की तैयारी की| और आज वो IIT गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। यानि एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की बच्ची आने वाले समय में खुद किसी फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी|

- दिल्ली के नंद नगरी स्कूल में पढ़ने वाले हिमांशु की भी परिस्थिति बहुत मुश्किल थी| वो जब ग्यारहवीं में पढ़ता था तो उसके पिता जी की मौत हो गई। अपना घर चलाने के लिए वो स्कूल के बाद मज़दूरी भी करता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होने से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और आज वो दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। और आने वाले समय में एक गरीब परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा दिल्ली शहर का एक बड़ा डॉक्टर बनेगा|

16. अध्यक्ष महोदय, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है| आज गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी ऊँचाइयों को छू रहे है| अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना चाहूँ तो मुझे यक़ीन है, उसके लिए आपको विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ़ एक साल 2023-24 में ही दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2 हज़ार 121 बच्चों ने JEE और NEET की परीक्षा क्लियर की है| अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा अब वो डॉक्टर बनेगा, इंजिनियर

बनेगा, अपना बिज़नेस करेगा और एक पीढ़ी में ही अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा| अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है।

17. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये| इसमें पहला कदम था - शिक्षा का बजट बढ़ाना| शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है| यही कारण है कि 2015 में सरकार में आते ही हमनें शिक्षा के बजट को डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है| 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6 हजार 554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के इस बजट में शिक्षा पर हम 16 हजार 396 करोड़ रूपये का प्रावधान कर रही है|

18. मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते है कि चाहे 2 रोड-फ्लाईओवर कम बन जाए लेकिन शिक्षा के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए| लेकिन प्रभु श्रीराम की दिल्लीवालों पर ऐसी कृपा रही है कि हमारी सरकार में दिल्ली में न कभी शिक्षा के लिए पैसों की कमी हुई है और न ही सड़कों या फ्लाईओवरों के लिए|

19. अध्यक्ष महोदय, आजादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे| लेकिन 9 सालों में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार ने 22 हज़ार 711 नए क्लासरूम बनाए है| जहां पहले बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, वही आज उनके लिए क्लासरूम में रंग-बिरंगे डिज़ाइनर डेस्क हैं। जहाँ पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे-फूटे बीकर्स और जार होते थे वही आज हर सब्जेक्ट - फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस के लिए अलग-अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैकबोर्ड भी घिस घिस कर ख़राब हो चुके थे, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम मौजूद है। जिन स्कूलों में सीढ़ियाँ टूटी मिलती थी, वहां आज बच्चों के लिए शानदार लिफ़्ट मौजूद है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है| पहले टीन-टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूलों में बदल गए है।

20. 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद,पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी| केजरीवाल सरकार ने फ़ैसला किया कि, हम अपने शिक्षकों को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी का मानना था कि जबतक हम अपने टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वो बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे| पिछले 9 सालों में हमने अपने 400 से ज्यादा प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा तक़रीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा। तक़रीबन 1700

प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा। और इस साल से दिल्ली नगर निगम स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हमनें आईआईएम में ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया है|

21. हमनें पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया| जो पेरेंट्स एक समय में सरकरी स्कूलों में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल गेट के अन्दर घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे है|

22. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ़ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैम्पस पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं।

23. 2014 में, जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना गरीब परिवार के लिए एक मजबूरी थी; वही इस साल SoSEs की 6 हज़ार सीटों पर एडमिशन के लिए 1 लाख 40 हज़ार एप्लिकेशंस आये हैं। जिस अनुपात में SoSEs में ऐप्लिकेशन आए; उतना शायद भारत की IITs में भी नहीं आते होंगे।

24. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे तीन और स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं- आर्म्ड फ़ोर्सेज़ प्रिपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि, आर्म्ड फ़ोर्सेज़ प्रिपरेटरी स्कूल के पहले बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की लिखित परीक्षा पास की।

25. शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है- स्कूलों में शिक्षकों-प्रिंसिपलों की रिकॉर्ड भर्ती| 2015 से पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34 हज़ार 182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47 हज़ार 914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7 हज़ार की भर्ती की प्रक्रिया चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में यूपीएससी से सीधे 324 प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई जो अपने आप में रिकॉर्ड है साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपलों को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रोमोट किया गया| जिससे सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में अब नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है|

26. वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल ऑफ़ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है| दिल्ली में पिछले 8 सालों से हर साल हमारे स्कूलों का बोर्ड का रिजल्ट

प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है| इसी का नतीजा है कि पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लिया है।

27. अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल जी की इस शिक्षा क्रांति के 9 सालों की कहानी सिर्फ़ स्कूलों तक सीमित नहीं है; बल्कि, दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानो तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज़ - अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71 हज़ार 416 थी| दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये महत्वपूर्ण द्योतक है कि, इन यूनिवर्सिटीज में 20 हजार से ज्यादा सीटें बढ़ी है| और आज यहाँ 93 हज़ार 880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में 12 हज़ार 204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या बढ़कर 62 हज़ार हो गई है| साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज़ - दिल्ली स्किल्स एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की।

28. तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ़ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है बल्कि इंट्रास्ट्रक्चर का भी व्यापक विस्तार किया है। 2016-2017 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दो नये कैंपस- करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गये। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई| साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के भी दो नये कैंपस 2020 में - जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू किए गये। 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की।

29. दिल्ली में शिक्षा की 10 साल में बदली हुई तस्वीर ने दिखा दिया है, कि अगर किसी सरकार की इच्छाशक्ति हो, तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकती है| अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में किसी एक व्यक्ति ने अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो है दिल्ली शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी| मैं आज इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूँ| क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना, इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव आना असंभव था|

स्वास्थ्य

30. अध्यक्ष महोदय, रामराज्य का दूसरा सिद्धांत है- हर बीमार का इलाज| तुलसीदासजी के रामचरितमानस में एक चौपाई है।

अल्प मृत्यु नहिं कव निउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा।

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना॥

31. अर्थात्: प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहदमंद रहने की व्यवस्था है| किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई दुःख होता है। सभी सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुःखी है और न गरीब है।

32. अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि, हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का भी बहुत बुरा हाल था। अस्पताल की गंदगी देख कर भरोसा नहीं होता था कि यहां किसी का इलाज हो सकता है। ऐसा लगता था कि जो सरकारी अस्पताल जाएं वह 4 बीमारियां और लेकर आ जाए। आप सब याद कीजिए सरकारी अस्पताल का वो दृश्य- गंदे फ़र्श, टूटे और बदबूदार टायलेट, पीली चद्दरें , OPD काउंटर पर घंटो तक भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं; दवाई के काउंटर पर लम्बी लाइन पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए उसे किसी भी प्राईवेट अस्पताल में ले जाऊँ। एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाला खर्च ही परिवार को ग़रीबी में धकेल देता था। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि, वह अपने पिता की जान और पुर्खो की जायदाद के बीच किसी एक को ही बचा पाए?

33. NSSO के 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक़, सिर्फ़ एक हॉस्पिटलाइज़ेशन होने पर दिल्ली के किसी भी साधारण परिवार को ₹38 हज़ार तक का खर्च उठाना पड़ता था| 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹2 लाख 47 हज़ार रूपये थी। यानि सिर्फ़ एक हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के आम परिवार को अपनी सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च करना पड़ता था।

34. लेकिन केजरीवाल सरकार ने ये प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के बाद 9 साल में, स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मज़बूती तक, और निराशा से विश्वास तक का सफ़र तय किया है।

35. आज, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत 38 अस्पताल है, जहां रोजाना 81 हज़ार से ज्यादा OPD मरीजों, और हर महीने 65 हज़ार 806 IPD मरीज़ो का इलाज फ्री में हो रहा है। 2014 में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 9 हज़ार 523 बेड थे। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 13 हजार 708 बेड्स हैं,

हमारे अस्पताल अब 1.5 गुणा ज़्यादा मरीज़ों की देखभाल कर पाते है। हमने हर अस्पताल के OPD काउंटर की टाइमिंग बढ़ाई और हर काउंटर को रिसेप्शनिस्ट दिया। मरीज़ों की देख-रेख के अन्तराष्ट्रीय मानकों से सीखकर हर अस्पताल में साफ़ सफ़ाई, सैनिटेशन और सुविधाओं की बेहतरी पर नए सिरे से काम हुआ। एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट तैयार करके हर अस्पताल में emergency medicines के procurement को भी सख़्ती से लागू किया, ताकि किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो।

36. महोदय, 2017 से केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की - इसके तहत अगर एक मरीज को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए एक महीने से ज्यादा की डेट मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी करवा सकता है और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की इस पहल के अंतर्गत अब लोग 1580 अलग अलग प्रकार की फ़्री सर्जरीज, प्राइवेट अस्पताल में फ्री करवा सकते हैं।

37. 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में diagnostic tests करवाने के लिए भी लोगों को महीनों का लम्बा इंतज़ार करना पड़ता था| लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने इस जर्जर व्यवस्था को बदल दिया है| अब न केवल अस्पतालों में टेस्ट होते है बल्कि फ्री भी होते है| अगर सरकारी अस्पताल व्यस्त हो, तो सरकार निजी अस्पतालों और सेंटर्ज़ के साथ टेस्ट का प्रबंध करती है। फ्री diagnostic टेस्ट्स के शुरु होने के बाद, से अबतक लोगों ने 5 लाख 66 हजार से ज्यादा टेस्ट करवाए है!

38. सिर्फ़ अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल तक पहुँचने के संघर्ष में भी केजरीवाल सरकार परिवारों के साथ खड़ी रही है। 2014 में सरकार के पास मौजूद लगभग 155 CATS एम्बुलेंस के मुक़ाबले, आज दिल्ली में 380 CATS एम्बुलेंस हैं। इस फ्लीट को हर साल बढ़ाकर, हम इस स्तर पर ले आए कि हमारे एम्बुलेंस का एवरेज रिस्पांस टाइम 10 साल में 55 मिनट से घटकर, मात्र 15 मिनट रह गया है|

39. अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति किसी की जान बचाता है उसे फरिश्ता कहते हैं, उसे भगवान का दर्जा देते है। लेकिन हम सब जानते है कि पहले, दिल्ली में रोड पर जब कोई एक्सीडेंट होता था, तो घायल की छटपटाते हुए ही मौत हो जाती थी, लोग एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल ले जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि, अस्पताल उनसे इलाज का खर्चा माँगेगा, वो केस में फँस जाएँगे। इसी वजह से सरकार में आने पर हमने दिल्ली में 'फ़रिश्ते दिल्ली के' स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल लेकर जाए| चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट वहां इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है| और अबतक हम इस स्कीम से 22 हजार लोगों की जान बचा चुके है|

40. जिनमें से एक सूरज कुमार है। सूरज कुमार का मयूर विहार फेज-1 में भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लंबा इलाज चला, कई ऑपरेशन हुए। ट्रीटमेंट का बिल 36 लाख रुपये आया| सूरज कुमार, एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कुछ हजार रूपये महीने कमाने वाला एक वर्कर था| वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा-पूँजी भी लगा देते पर इतना बड़ा बिल नहीं चुका पाते। लेकिन फ़रिश्ते योजना के तहत सरकार ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया। सूरज को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा|

41. हर व्यक्ति की जान बचाना ही रामराज्य है| जहाँ हर जिन्दगी अनमोल है और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास होता है, वही रामराज्य है|

42. अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट परिवार को ग़रीबी में धकेल देती थी, ठीक उसी तरह, छोटी से छोटी बीमारी भी एक सामान्य परिवार का महीने का बजट बिगाड़ देती थी। परिवार के किसी सदस्य को बुख़ार भी होता था तो कोई प्राइवेट डॉक्टर 500 रूपये की फ़ीस लेता था, एक पर्ची पर लम्बी दवाइयों की लिस्ट दे देता था जो 500 से 1000 रूपये से कम की नहीं आती थी; और दो तीन टेस्ट बता देता था जिसमें कम से कम 500 रूपये का खर्च आता था। परिवार के एक सदस्य को बुख़ार आने पर ही 2000 रूपये का खर्च आ जाता था। एक सामान्य परिवार जिसकी प्रति माह आय 25 हज़ार से 30 हज़ार होती है, डॉक्टर के पास जाने के लिए कई बार सोचता था। इसका ख़ामियाज़ा सबसे ज़्यादा महिलाएँ उठाती थीं; क्योंकि पैसे बचाने के लिए वे अक्सर डॉक्टर के पास जातीं ही नहीं थी। और यही कारण था कि कुछ सालों में छोटी स्वास्थ्य समस्याएँ बड़ी बीमारियाँ बन जाती थी।

43. लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है, कि केजरीवाल सरकार ने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया - एक ऐसा मॉडल जहाँ आपकी गली-मोहल्ले में, आपके घर के पास ही AC क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है; जहाँ आपका इलाज फ़्री है, आपकी दवाइयाँ फ़्री है, आपके टेस्ट भी बिलकुल फ़्री होते है।

44. 9 साल स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के बाद, आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि रामराज्य को साकार करने के प्रयास में हमने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां रोजाना 64 हज़ार लोगों को मुफ़्त में दवाई, टेस्ट और इलाज मिल रहा है। अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से ज्यादा ओपीडी हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश-विदेश से लोग दिल्ली आए हैं, चाहे वो तेलंगाना, पंजाब या तमिलनाडू के मुख्यमंत्री हों, या

यूनाइटेड नेशन के दो पूर्व सैक्ट्री जर्नल कोफी अन्नान और बान-की-मून। शायद ही कोई ऐसा हेल्थ केयर मॉडल होगा जिसे देश-विदेश में इतनी तारीफ मिली हो।

45. दिल्ली के स्वास्थ्य क्रांति का ज़िक्र एक नाम के बिना अधूरा रहेगा - और वो है मेरे बड़े भाई सत्येन्दर जैन जी। जिस तरह राम भक्त हनुमान जी आपदा की घड़ी में संजीवनी का पर्वत ही उखाड़ ले आए थे, ठीक उसी तरह सत्येंदर जैन जी ने अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में दिल्ली की चरमराती हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जिवित किया| मैं सभी दिल्लीवासियों की तरफ से आज सत्येन्दर जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं।

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान

46. राम राज्य का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है - महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान। जब से अरविन्द केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनें है उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए काम किया है; लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, तो वो दिल्ली की महिलाएं है, अपनी माताओं- बहनों के लिए किया है। एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है कि, सदियों से जो महिलाएँ खुद की जरूरतों को सबसे पीछे रखती थी आज उन्हें अरविन्द केजरीवाल जी ने सबसे आगे रखा है। आज, जब केजरीवाल सरकार का दसवाँ बजट पेश हो रहा है, तो मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ, कि 2014 और 2024 की तुलना करें तो दिल्ली की महिलाओं की जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को सुलझाकर, उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी जीने का अवसर दिया है।

47. चाहे वो फ्री बिजली-पानी देकर महंगाई के इस दौर में महिलाओं के घर खर्चे की चिंता दूर करनी हो या फिर बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास शिक्षा देकर, उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी हो। चाहे पानी के लिए टैंकरों के पीछे घंटों लम्बी लाइनों से आजादी दिलानी हो, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के ज़रिये उनके स्वास्थ्य का ख़याल रखना हो या फिर बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पर भेजकर दशकों से उनके मन में तीर्थ पर जाने की ख्वाहिश पूरी करनी हो; इन सभी दिशा में दिन-रात मेहनत कर अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 9 सालों में दिल्ली की हर महिला को खुलकर जीने की आज़ादी दी है।

48. महोदय, 2015 में सरकार बनने के बाद जब मैं कुछ सरकारी गर्ल्स स्कूलों में गई - उस दौरान मैंने एक क्लास में बैठी लड़कियों से ये पूछा कि, उनमें से कितनों के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते है। मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि कम से कम 95% लड़कियों ने अपना हाथ उठा लिया। इसका क्या मतलब

था; कि अगर किसी परिवार के पास थोड़े से भी पैसे थे, तो वो अपने बेटों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, वहीँ उन बेटियों को नजरअंदाज कर जर्जर सरकारी स्कूलों की ओर धकेल दिया जाता था। लेकिन आज उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल रही है; हम अपने स्कूलों में 9 लाख से अधिक लड़कियों को शानदार शिक्षा दे रहे हैं। इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों से 933 लड़कियों ने नीट व 123 लड़कियों ने जेईई की परीक्षा पास की है| आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर बन रही है, इंजिनियर बन रही है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रही है, और अपने खुद का बिज़नेस शुरू कर और महिलाओं को भी रोज़गार दे रही है।

49. महोदय, 2014-15 में एक आम परिवार की लड़की जब अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज जाना चाहती थी, तो माँ-बाप इसलिए मना कर देते थे क्योंकि आने जाने में खर्च बहुत होता था। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए काम करने नहीं जाती थी; क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा आने जाने के किराये में चला जाता था। समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बढ़े, इसके लिए देश के इतिहास में पहली बार, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिलकुल फ्री कर दी गई - ताकि एक महिला को दिल्ली में कही भी जाना हो, उसके लिए उसे पैसों की चिंता न करनी पड़े और अपने भाई अरविन्द केजरीवाल से मिले 'पिंक टिकट' के साथ वो बेझिझक यात्रा कर सके। अब किसी महिला को घर से बाहर निकलने से पहले पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता|

50. पिछले कुछ सालों में पिंक टिकट की संख्या लगातार बढ़ी है, 2020-21 में ये 17 करोड़ 70 लाख थी, जो 2022-23 में 40 करोड़ 20 लाख हो चुकी है; यानि, हर रोज़ लगभग 11 लाख महिलाएँ हमारी बसों में फ्री सफ़र कर पा रही है। 2019 से शुरू होकर अबतक मात्र 5 साल में ही 153 करोड़ बार, महिलाओं ने फ्री में बस यात्रा की है|

51. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, फिर भी एक बड़े भाई का धर्म निभाते हुए अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के कई प्रयास किए है। मुख्यमंत्री CCTV योजना के तहत, आज दिल्ली में 2 लाख 60 हज़ार से अधिक CCTV कैमरा लगे है; और Forbes India की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक़, शहर के हर square mile में 1820 से अधिक कैमरा लगाए गए है। अब CCTV surveillance per square mile के आँकड़े में दिल्ली ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है|

52. Safety Pin नामक एक NGO की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 2014 में लगभग 7 हजार 500 dark spots थे, जहां अंधेरे की वजह से महिलाएँ गुजर भी नहीं पाती थी। इन इलाक़ों में अपराधियों को जुर्म

करने की खुली छूट मिलती थी; और यहाँ जाने से पहले एक औरत को 10 बार सोचना पड़ता था। इस डर को ख़त्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सड़कों को बड़े स्तर पर रौशन किया| 2014 तक PWD की सड़कों पर 66,000 लाइटें थी लेकिन आज PWD दिल्ली की 1400 km सड़कों पर 87,000 से ज़्यादा लाईटें हैं, यानि हर किलोमीटर पर 62 से ज़्यादा लाईटें है। कॉलोनियों के अंदर भी, "मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाईट्स योजना" के तहत 2 लाख 80 हजार LED स्ट्रीट लाईट्स लगाए जा चुकी है।

53. अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से अपने घर आती है; तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं| क्योंकि वो चाहते है कि उनकी बहन, उनकी बेटी को अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। और आज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा भाई, एक बेटा होने का फ़र्ज़ निभाते हुए, वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं - इस योजना के तहत, 18 साल की उम्र से ज़्यादा की महिला को 1000 रूपये प्रति माह की सम्मान राशि मिलेगी। तो चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी बिटिया को एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए किसी बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, या एक घर में रहने वाली महिला को सिनमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो; अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे क्योंकि उनके भाई अरविंद केजरीवाल उन्हें प्रतिमाह 1000 रूपये देंगे।

54. अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में लिखा है- जहाँ महिलाओं की पूजा होती है,सम्मान होता है; वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ महिलाओं का सम्मान नही होता, वहाँ किए गए सारे अच्छे काम भी निष्फल हो जाते हैं। मुझे भरोसा है कि, दिल्ली में हो रहे महिला सुरक्षा और सम्मान के इन प्रयासों से भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी दिल्लीवालों को मिलेगा।

बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा

55. अध्यक्ष महोदय, उम्र के एक पड़ाव पर आकर हर बुजुर्ग सोचता है कि तीर्थ यात्रा कर आऊं, भगवान के दर्शन कर आऊं। लेकिन कई बार मन में इच्छा होने के बावजूद भी वे जा नहीं पाते, तीर्थ यात्रा कर नहीं पाते। कभी पैसे की कमी होती है, कभी कोई साथ देने वाला नहीं होता है, कभी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता है। लेकिन यह दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के रूप में उनको सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मिला, अपने परिवार का बड़ा बेटा मिला है। एक ऐसा बेटा जिसने दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेदारी ली है। इसलिए 2019 में मुख्यमंत्री

तीर्थ यात्रा योजना की शुरूआत हुई। जिसके तहत हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेनें अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी, द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी इत्यादि जगह पर जाती हैं।

56. तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों को सिर्फ एक फॉर्म भरना है। वे अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर जा सकते हैं। बाकि सारा इंतजाम दिल्ली सरकार करती है, चाहे वह AC ट्रेन का हो, लोकल टूर का हो, खाने पीने का हो या जरुरत के सभी सामान का। आज मैं यह बात गर्व के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2019 से आजतक 92 ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली के 87 हजार से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं।

57. अध्यक्ष महोदय, रामायण की सबसे ज्यादा मार्मिक कहानी शायद श्रवण कुमार की है। जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता-पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, आज के इस आधुनिक युग में अगर कोई श्रवण कुमार है तो वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं।

कोई भी भूखा न सोए

58. अध्यक्ष महोदय, कहते हैं असली रामराज्य वहां, भूखा ना कोई सोये जहाँ।

59. दिल्ली में रामराज्य को यथार्थ करने के प्रयास में, कभी कोई इंसान भूखा ना रहे, और हर ज़रूरतमंद को भरपेट खाना मिले, इसलिए हमनें बहुत-सी योजनायें चलाई है|

60. दिल्ली में 10,897 आंगनबाडियां हैं, जिनके माध्यम से हम 8 लाख महिलाओं और बच्चों के पोषण की व्यवस्था करते हैं| रोज 3 से 6 साल के 1 लाख 80 हजार बच्चों को पौष्टिक गरमा-गर्म खाना मिलता है| 3 साल तक के 3 लाख 40 हजार बच्चों को पंजीरी-नुमा Nutritional Supplement और 1 लाख 20 हजार गभर्वती और Lactating माताओं को Nutritional Supplement दिया जाता है। इसके लिए हमने दिल्ली में 11 शानदार वर्ल्ड क्लास किचन बनाये हैं। साथ ही देश के टॉप Nutritionists से बच्चों के लिए खाने की मेन्यू तैयार करवाई गई है। जिससे बच्चों के लिए ज्वार, बाजरा, रागी, राजमा, छोले, दाल जैसे हाई प्रोटीन चीजों से उनकी पसंद के आहार बनाए जाते है।

61. साथ ही दिल्ली में मिड डे मील योजना के तहत हम रोजाना दिल्ली सरकार और एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 20 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाते हैं। आंगनवाडियों और स्कूलों के इन प्रयासों से दिल्ली में कुपोषण बहुत कम हुआ है। 2014 में दिल्ली में severe और

moderate malnutrition से प्रभावित तक़रीबन 2 lakh बच्चे थे, आज ये संख्या 91.5% तक घटकर मात्र 16 हजार 814 रह गई है| ये किसी चमत्कार से कम नहीं है|

62. महोदय, इसी तरह केजरीवाल सरकार डूसिब के 198 शेल्टर होम्स में रहने वाले 17 हजार बेघर लोगों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करती है। सर्दियों में ये संख्या 20 हजार से भी अधिक हो जाती है।

63. 2024-25 में पोषण से जुड़ी इन सभी योजनाओं के लिए हमने लगभग 664 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

शहीदों का सम्मान

64. अध्यक्ष महोदय, शहीदों के सम्मान से बड़ा पुण्य काम किसी भी व्यक्ति या सरकार के लिए नहीं होता। केजरीवाल सरकार, देश की पहली ऐसी सरकार है जो शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को एक करोड़ की सम्मान राशि देती है। सरकार में आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश की रक्षा करते हुए, अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना शुरू किया। दिल्ली सरकार की यह योजना ड्यूटी पर तैनात सभी जांबाजों को यह आत्मविश्वास देती है कि वह देश के लिए जान की बाजी लगा दे तो सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी।

65. महोदय, आज मैं इस सदन के समक्ष उन कुछ जाबांजों की कहानी साझा करने जा रही हूँ-

- द्वारका निवासी मेजर रघुनाथ भारतीय सेना की तीसरी बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट में थे। संभावित घुसपैठ के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, 5 मई 2022 को सुखदार, जम्मू-कश्मीर में उन्होंने एक अभियान शुरू किया। जहाँ लाइन ऑफ़ कण्ट्रोल के पास एक सैन्य ऑपरेशन में वो शहीद हो गए

- नांगलोई निवासी श्री दिनेश कुमार, सीआरपीएफ़ के 205 कोबरा बटालियन में बतौर इंस्पेक्टर नियुक्त थे। 2013 में छतीसगढ़ में एक आईईडी ब्लास्ट में वे गंभीर रूप से घायल हो गये और लंबे समय तक बीमार रहे। 2017 में उनका निधन हो गया।

- अध्यक्ष महोदय, फायर मैन, प्रवीण कुमार, भोरगढ़ फायर स्टेशन में तैनात थे। उसी दौरान CISF कैंप के पास फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। प्रवीण कुमार ने जांबाजी के साथ आग बुझाई लेकिन वो स्वयं झुलस गए,और उसके बाद Septic Shock के कारण इलाज के दौरान वे शहीद हो गए।

66. दिनेश कुमार, मेजर रघुनाथ, प्रवीण कुमार सहित 35 शहीदों को केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 सालों में 1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि दी है| सिर्फ़ जाँबाज़ सेनानियों के परिवारों की नहीं। कोविड के दौरान वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो दिल्ली वालों की जान बचाते हुए शहीद हो गए, उनके परिवारों को भी केजरीवाल सरकार ने 1-1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि दी है।

67. साथ ही, कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 92 COVID Warriors के परिवारों को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने 'सहायता-सम्मान राशि' से 1-1 करोड़ रूपये दिए गए है।

68. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ऐसे जांबाज पहले भी थे लेकिन आजतक किसी ने उन्हें पहचान नहीं दी, उनके परिवार को सम्मान नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने, देश की सेवा कर रहे दिल्ली के जाँबाजों को ये भरोसा दिया है कि, भगवान ना करे, अगर मुझे अपनी ड्यूटी करते वक्त कुछ हो गया, तो मेरे मुख्यमंत्री, मेरे घर का, मेरे परिवार का ख़याल रखेंगे।

<u>किसी के साथ अन्याय ना हो</u>

69. राम राज्य का अगला सिद्धांत है कि किसी के साथ अन्याय न हो|

70. रामायण में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के राज्य में हर इंसान, पशु, और जीव को न्याय स्वयं भगवान राम के दरबार से ही मिलता था, प्रभु श्रीराम के दरबार के द्वार हमेशा सभी के लिए खुले रहते थे ताकि वे अन्याय से अपनी प्रजा की रक्षा कर सके।

71. आज के आधुनिक युग में लाखों लोग कोर्ट में न्याय की उम्मीद लेकर आते है। पर दुर्भाग्य है कि Judicial Infrastructure और Judges की कमी के कारण, देशभर में लगभग 5 करोड़ कोर्ट केस लंबित है, जिस कारण लोगों को न्याय की आस में सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है - Justice Delayed is Justice Denied, यानि न्याय का समय पर ना मिलना, अपने आप में अन्याय है।

72. लेकिन दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 2014-15 में न्याय व्यवस्था के लिए कुल बजट 760 करोड़ रूपये होता था| केजरीवाल सरकार ने न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए साल दर साल इसका बजट बढ़ाया है| और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज ये 4 गुणा तक बढ़कर, 3 हजार 98 करोड़ हो गया है।

73. 2024-25 में केजरीवाल सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज़ एवेन्यू में 4 शानदार Court Complexes का निर्माण शुरू करवा रही है।

74. एक मज़बूत Legal Infrastructure तैयार करने के साथ-साथ, केजरीवाल सरकार लोगों को कोर्ट के केस लड़ने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाती है। अक्सर एक आम आदमी महँगे वकीलों का खर्चा नहीं उठा पाता, जिससे या तो वो केस लड़ नहीं पाता, या केस वापस लेने को बाध्य होता है। लेकिन दिल्ली सरकार, Delhi State Legal Services Authority के माध्यम से, जरुरतमंदो को बिना किसी खर्च के वकील मुहैया करवाती है| ताकि वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सके, और न्याय की राह पर पैसे की कमी एक बाधा ना बने। DSLSA के माध्यम से 2016 में सिर्फ़ 33,000 लोगों को फ्री लीगल सर्विस मिली थी, लेकिन अब ये आंकड़ा लगभग चार गुणा हो गया है और 2022-23 में 1 लाख 25 हजार लोगों को फ्री लीगल सर्विस मिली है|

75. केजरीवाल सरकार के आने से पहले एक आम आदमी को सरकारी दफ़्तरों में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक छोटे से काग़ज़ के लिए धक्के खाना, लाईनो में खड़े रहना, सरकारी दफ़्तरों में बैठे कर्मचारियों की उपेक्षा झेलना, और हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती था| लेकिन हमने "डोर-स्टेप डिलीवरी ऑफ़ सर्विसेज़" के माध्यम से दिल्लीवालों को सरकारी दफ़्तरों में हो रहे इस अन्याय से बिलकुल मुक्त कर दिया है।

76. अब पहले की तरह, किसी भी सरकारी काग़ज़ात बनवाने के लिए लम्बी लम्बी लाइनों में लगने या सरकारी दफ़्तरों के धक्के खाने नहीं पड़ते, ना ही किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो बस 1076 हेल्पलाइन पर एक कॉल करना होता है। सरकार आपके घर आकर आपका काम करवाती है। मुझे ये बताते हुए ख़ुशी है कि, साल 2018-19 में शुरू होने के बाद से 1076 हेल्पलाइन के जरिए 6 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों को सरकारी डॉक्यूमेंट्स जारी हुए है।

रोजगार

77. अध्यक्ष महोदय, ये पिछली सरकारों की नाकामी ही है कि, देश में बेरोज़गारी इतने बड़े स्तर पर है। आज पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली में युवाओं को स्किल्ड और जॉब रेडी बनाने की दिशा में हमारे Industrial Training Institutes (ITIs) शानदार भूमिका निभा रहे है। वर्तमान में केजरीवाल सरकार शहर भर में 19 Industrial Training Institutes चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फ़ैशन डिज़ाइनिंग, कम्प्यूटर ऑपरेशंश, प्रोग्रामिंग और 3D मॉडलिंग तक, ITI के छात्रों को हर क्षेत्र में टेक्निकल शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। और पिछले साल ITI से निकलने वाले 10,000 से ज्यादा छात्रों को Toyota, Maruti, Microsoft, etc जैसी मशहूर कंपनियों में नौकरियां मिली है!

78. अध्यक्ष महोदय, हमनें पिछले 9 सालों में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए है। 21वीं सदी की ज़रूरतों को समझते हुए हमनें इनमें रोबोटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ऑटो-मोबाइल इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में कई आधुनिक डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए है, ताकि हमारे युवा आने वाले कल की इकॉनमी के लिए आज से ही तैयार हो सके।

79. महोदय, केजरीवाल जी की सरकार बनाने के बाद Delhi Skill and Entrepreneurship University की शुरुआत की थी। आज, इस यूनिवर्सिटी में 18 हजार 529 छात्र शानदार स्किल रिलेटेड कोर्सज पढ़ रहे है। इस वर्ष, हमारे छात्रों को 10 लाख तक का salary package भी मिला! महोदय, ये कामयाबी सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक सीमित नहीं है।

- 2023-24 में दिल्ली सरकार की Indira Gandhi Delhi Technical University For Women (IGDTUW) का placement rate 85% रहा| इस वर्ष यहाँ highest salary package 82 लाख रूपये रहा है।
- IIIT दिल्ली का placement rate 2023-24 में 75% रहा । इस वर्ष IIIT दिल्ली का highest package 49 लाख रूपये रहा।
- NSUT का placement rate 2023-24 में 75% था; इस वर्ष यहाँ का highest salary package 80 लाख पहुँच गया है।

80. हालाँकि दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी नौकरियां मिल रही है, लेकिन इस बात को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि, आज ये देश एक Job Crisis के बीच खड़ा है। McKinsey की 2020 की इकॉनॉमिक रिपोर्ट कहती है कि, 2030 तक पूरे देश में 9 करोड़ Non-Farm नौकरियाँ चाहिए होंगी। ये नई नौकरियाँ कहा से आएँगी, अगर देश का हर युवा, सिर्फ़ नौकरियों की लाईनों में खड़ा रहेगा, और एक से दूसरे सरकारी परीक्षा के फॉर्म भरता रहेगा|

81. अध्यक्ष महोदय, सिर्फ़ Entrepreneurship ही हमारे देश की बेरोज़गारी मिटा सकता है। इस दिशा में 2019 में हमने अपने स्कूलों में एंत्रप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बच्चों को इतना कॉफिडेंट और काबिल बनाना है, की वो पढ़ाई के बाद नौकरी माँगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें। इस करिकुलम के प्रैक्टिकल कंपोनेंट 'बिज़नेस ब्लास्टर्स' के तहत

दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को 2000 रुपये का सीड मनी दिया जाता है| जिससे वो अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कोई छोटा स्टार्टअप शुरू कर सके|

82. बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के बहुत शानदार नतीजे देखने को मिले है| हमारे छात्र लोजिस्टिक्स बिज़नेस, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल, ब्लूटूथ स्पीकर, डार्क चॉकलेट, नुट्रीशनल सप्लीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि के फील्ड में न सिर्फ अपने शानदार स्टार्टअप्स से पैसे कमा रहे है बल्कि स्कूल से पास आउट होने से पहले ही बहुत से लोगों को नौकरियां भी दे रहे है|

83. बिज़नेस ब्लास्टर्स के तहत साल 2023-24 में 2 लाख 40 हजार स्टूडेंट्स ने लगभग 38 हजार टीमें बनाकर, अपने बिज़नेस आइडियाज़ पर काम किया है! और आने वाले साल में भी इस योजना के तहत हम स्टूडेंट स्टार्टअप्स में 40 करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे|

84. इस मॉडल को और सशक्त बनाने के लिए, केजरीवाल सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी Incubation Centres की शुरुआत की हैं; जहां 122 छात्रों को उनके स्टार्टअप्स के लिए, Industry leaders की mentorship से लेकर funding तक के लिए सपोर्ट मिल रहा है - ताकि वे भविष्य के Microsoft, Apple, और Amazon बनकर लाखों युवाओं को नौकरी दे पाए।

85. अनंत शर्मा, केजरीवाल सरकार के IIIT दिल्ली में पढ़ रहा एक सामान्य छात्र था। 2019 में अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में ही उसने 'ट्वीक लैब्स' नाम के start-up की शुरुआत की - जो एक नए क़िस्म की sports technology का आविष्कार था। IIITD में मौजूद इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में एक छोटी शुरुआत कर, इनकी कम्पनी ने इतनी तरक़्क़ी कर ली कि अनंत को मशहूर Business Reality Show - Shark Tank में जगह मिली। उन्होंने देश के सबसे विख्यात उद्योगपतियों के सामने अपना business pitch किया, और 60 लाख रूपये की फंडिंग प्राप्त की|

86. अनंत प्रमाण है कि, अगर क़ाबिलियत को सरकार का साथ मिले, तो दिल्ली और देश के कॉलेजों में पढ़ रहे युवा, अपने शानदार बिज़नेस आइडियाज़ के दम पर दुनिया बदल सकते है। और हमारे कॉलेजों से अनेकों ऐसे अनंत निकले, इसलिए इस वर्ष से केजरीवाल सरकार के सभी यूनिवर्सिटीज और ITIs में Business Blasters Senior की शुरुआत होगी। जिसके तहत हमारे छात्रों को अपना स्टार्ट अप शुरू करने के लिए सीड मनी और सपोर्ट मिलेगा| Business Blasters Senior के स्टार्टअप्स में केजरीवाल सरकार इस वर्ष 15 करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट करेगी।

87. अध्यक्ष महोदय, आइये हम 10 साल बाद के दिल्ली की कल्पना करें| अगर हमारे स्कूलों में हर वर्ष में निकले 40,000 से ज्यादा business ideas में मात्र 5% भी सफल हो गए, तो 10 साल बाद दिल्ली

और देश में 2000 बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाएँगी और भविष्य में यही कंपनियां देश से बेरोज़गारी और ग़रीबी को जड़ से मिटा देंगी|

88. अध्यक्ष महोदय, यही असली राम राज्य होगा|

दिल्ली का हर घर रौशन

89. रावण के वध के बाद जब प्रभु श्रीराम अयोध्या आए तो हर घर में दिए जलाए गए, दीपावली मनाई गई| कहते है रामराज्य का मतलब ही है, कि हर घर रौशन होगा| आज दिल्ली में लोगों को अपना घर रौशन करने के लिए दीपावली का इंतजार नहीं करना पड़ता, और यहाँ 24 घंटे बिजली आती है और हर घर रौशन रहता है|

90. आप सबको याद होगा कि, दिल्ली में लम्बे-लम्बे पॉवर कट एक सामान्य बात होती थी। ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2014 तक कि गर्मियों में दिल्ली में न सिर्फ 8-8 घंटे लम्बे पॉवर कट होटे थे| बिजली के इतने बड़े बिल आते थे कि, एक सामान्य परिवार को अपने घर के बाक़ी खर्चे काटने पड़ते थे।

91. 2014 में जब दिल्लीवासी पावर कट और महंगी बिजली से जूझ रहे थे, तब बिजली की पीक डिमांड लगभग 5 हजार 800 MW थी। लेकिन पिछले 9 सालों में केजरीवाल सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि - 2023-24 में, दिल्ली ने 22 अगस्त को 7 हजार 438 MW की अपने peak demand को बिना किसी पॉवर कट के पूरा किया है।

92. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि, आज केजरीवाल सरकार दिल्ली में 24 घंटे बिजली देती है, देश में सबसे सस्ती बिजली देती है और 22 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल ज़ीरो आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जिन राज्यों में बिजली का दाम सरकारें कम रखती हैं, वहाँ बिजली कि डिस्ट्रब्यूशन कंपनी और उनका इन्फ्रस्ट्रक्चर पैसे कि कमी कि वजह से जर्जर हालत में पहुँच जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की जनवरी में निकली रेटिंग में दिल्ली के तीनों Discoms को 'A+ rating' मिली है, देश में टॉप 3 Discoms दिल्ली के है, तीनों प्रॉफिट में है और दिल्लीवालों को बिजली फ्री मिलती है| अध्यक्ष महोदय, ये रामराज्य नहीं तो और क्या है|

93. राम राज्य से प्रेरित सरकार की ज़िम्मेदारी अपने लोगों के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति भी है। यही कारण है कि केजरीवाल सरकार ने ना सिर्फ़ दिल्लीवासियों की समृद्धि के लिए बिजली कि उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन और Renewal एनर्जी पर भी फोकस

किया है। आज, दिल्ली की पावर सप्लाई में लगभग 30 % बिजली ग्रीन और Renewal एनर्जी से आती है। आज दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 255 MW बिजली रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से produce होती है। दिल्ली सरकार की 1280 सरकारी बिल्डिंग की छत पर सोलर रूफ्टाप प्लांट्स लगे हैं, और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि, 2024-25 में दिल्ली सरकार कि हर बिल्डिंग की छत पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का ये टार्गेट है कि 2027 तक 4500 MW, यानि कुल पावर सप्लाई का 25% सोलर एनर्जी से होगा।

पानी

94. अध्यक्ष महोदय, हिन्दू धर्म में मान्यता है कि, प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है।

95. पानी सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं, सम्मानजनक जीवन की आधारशिला भी है। 2014 में इस सम्माजनक जीवन के लिए, दिल्ली में लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। चाहे अनाधिकृत कॉलोनियां, जहाँ वर्षों से पानी की लाइनें नहीं बिछी थी, या झुग्गी बस्तियाँ हो, जहां रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को सुबह चार बजे उठकर, अपने घर के पास टैंकरों के इंतज़ार में लम्बी लाइन लगानी पड़ती थी, टैंक में पाइप डालकर पानी निकालने के लिए टैंकर माफिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे| हम अक्सर अख़बारों में पढ़ा करते थे, कि टैंकर से पानी भरने में इतनी लड़ाईयां हो जाती थी कि, लोगों की मौत हो जाती थी। दिल्ली की एक तिहाई आबादी रोज इस अमानवीय परिस्थिति से जूझती थी।

96. एक व्यक्ति के पानी का अधिकार अमीरी या ग़रीबी तय नहीं कर सकती। पानी का अधिकार दिल्ली के नवजीवन कैम्प की झुग्गियों में रह रहे एक परिवार का भी उतना है, जितना महरानी बाग में रह रहे परिवार का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी विज़न के साथ; दिल्ली में पहली बार 20,000 लीटर पानी फ़्री देना शुरू किया। आज दिल्ली में 62.5% घरों में, यानि लगभग 17 लाख परिवारों को पानी बिलकुल फ्री मिलता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार के आने के बाद, दिल्ली के कुल 9 लाख 34 हजार घरों को पहली बार पानी की सप्लाई मिली है| आज दिल्ली में पानी की उपलब्धता 840 एमजीडी से बढ़कर 1009 एमजीडी हो गई है||

97. अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में युद्ध स्तर पर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा झुग्गी क्लस्टर हो, जहां घर घर तक पानी की लाईन ना पहुँची हो। आज 99.6% अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन मौजूद है| 1 हजार 31 अनाधिकृत कॉलोनियों को अब सीवर नेटवर्क से जोड़ कर , इनमें 4243 किलोमीटर सीवर की लाईन डाली गई है|

केजरीवाल सरकार ने 2014 के बाद से, 2422 किलोमीटर पानी की और 3100 किलोमीटर सीवर की जर्जर लाइनों को बदलकर नई लाइनें डलवाई है। ताकि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएँ मिल सके|

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

98. अध्यक्ष महोदय, रामायण में अयोध्या के सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन है| किसी भी आधुनिक शहर का सौन्दर्य उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है| शहरो में नई सड़कें और फ़्लाईओवरों का निर्माण, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ-साथ, शहर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है|

99. पिछले 10 साल के दिल्ली के बदलते हुए चित्र में एक बड़ा बदलाव दिल्ली में सड़कों और फ्लाईओवरों के एक विशाल नेटवर्क के तौर पर आया है। पिछले 9 साल में केजरीवाल सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिए 30 नए फ्लाईओवर/ एलिवेटेड कॉरिडोर/अंडरपास का निर्माण किया है। इनमें रिंग रोड पर भलस्वा, बुराड़ी, मुकुंदपुर, जगतपुर फ्लाईओवर, मधुबन चौक से मुकरबा चौक के बीच एलिवेटेड कोरिडोर, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री पार्क-सीलमपुर फ्लाईओवर, दक्षिणी दिल्ली में आश्रम चौक अंडरपास व् फ्लाईओवर , सराय काले खां फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड पर आरटीआर फ्लाईओवर, बेनिटो जुआरेज अंडरपास आदि शामिल है|

100. इन फ्लाईओवर्स के बनने से न केवल traffic congestion कम हुआ है, बल्कि जिन सड़कों को पार करने में घंटों लग ज़ाया करते थे वो अब फ्लाईओवर्स बन जाने से मिनटों में पार हो जाता है। 2017-18 तक दिल्ली दुनिया का 4th सबसे कंजस्टेड शहर था। दिल्ली की आबादी और गाड़ियाँ दोनों की संख्या बढ़ी है लेकिन सड़कें, कारिडोर, फ्लाइओवर बनने से आज दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन में भारी कमी आई है, और अब दिल्ली दुनिया में 44वे नंबर पर आ गया है। यानि सड़क पर गाड़ियाँ बढ़ने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने सड़क पर कंजेशन कम किया है|

101. न सिर्फ दिल्ली की बड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स, बल्कि दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों को जोड़ने वाली इंटरनल सड़कों के निर्माण पर भी फोकस किया| मुख्यमंत्री सड़क पुर्ननिर्माण योजना के तहत अब तक लगभग 850 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

102. दिल्ली के हर निवासी को सार्वजानिक यातायात की अच्छी सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा बदलाव आया है| मार्च 2015 तक दिल्ली मेट्रों का कुल रेल नेटवर्क 193 किलोमीटर था और इसमें 143 मेट्रो स्टेशन थे। अब, पिछले 9 वर्ष में दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई दोगुनी होकर 393 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या भी बढ़कर 288 हो गई है।

103. मेट्रों में 2014 में रोजाना 24 लाख लोग यात्रा करते थे और आज 60 लाख से अधिक लोग रोज यात्रा करते है। मेट्रो आज दिल्ली के हर कोने तक पहुंच गई है, चाहे वो टिकरी बार्डर हो, समयपुर बादली हो, टीकरी कलॉ हों, बदरपूर बार्डर हो या शिव विहार हो।

104. दिल्ली में न केवल मेट्रो का दायरा बढ़ा है, यहाँ बसों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि, 1650 ई-बसों के साथ दिल्ली में आज इलेक्ट्रिक बसों का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा है| आज दिल्ली में 7582 आधुनिक बसों की शानदार फ़्लीट है, जो दिल्ली के अबतक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। साथ ही केजरीवाल सरकार द्वारा 2080 9-मीटर की ई-बसें ख़रीदी जा रही है, जो लास्ट माईल क्नेक्टीविटी के लिए मोहल्ला बस के तौर पर इस्तेमाल होंगी। मुझे ये बताते हुए भी ख़ुशी है कि, 2025 तक दिल्ली में 10,000 से भी अधिक बसें होंगी, जिनमें से इलेक्ट्रिक बसें 80% होंगी।

<u>अनाधिकृत कॉलोनियां - अंतिम व्यक्ति तक सुविधा</u>

105. भगवान श्री राम के जीवन ने सिखाया है कि जो समाज में सबसे उपेक्षित हैं, उनके बारे में सबसे पहले सोचना हमारा धर्म है। इससे प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की दशा और दिशा बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाधिकृत कॉलोनियों में रहता है| आज दिल्ली में लगभग 1800 अनाधिकृत कॉलोनियां है, जिसमें दिल्ली की 30% आबादी रहती है| एक समय ऐसा था, जब नेताओं को ये कॉलोनियां बस वोट मांगते समय याद आती थी, लेकिन चुनाव जीत कर जब सरकार बनती थी, तो कह दिया जाता था कि, इन कॉलोनियों में सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता| यहाँ न पीने का पानी था, न सड़कें थी, न सीवर न नालियाँ| ये कॉलोनियां गंदगी से अटी रहती थी| इनमें से ज़्यादातर कॉलोनियों में वो प्रवासी लोग रहते थे, जो दिल्ली में एक बेहतर जिन्दगी के लिए सपना संजो कर आए थे| लेकिन यहाँ उनके पास बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं थी।

106. लेकिन 2015 में जब अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को, हर संभव सुविधा देने को हमनें अपनी प्राथमिकता बनाई| यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लोगों को एक सम्मानजनक जीवन दिया। इन कॉलोनियों में हमनें पानी और सीवर की लाइनें डलवाई, नालियाँ बनवाई, और साथ-साथ 1355 ऐसी कॉलोनियों में 5 हजार 175 किलोमीटर सड़कें बनवाई। लेकिन ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है| अभी केजरीवाल सरकार इन

कॉलोनियों का और भी विकास करेगी| मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आने वाले वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट में 902 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

107. अध्यक्ष महोदय, महाराज दशरथ द्वारा माता कैकई को दिए एक वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्रीराम सब कुछ त्यागकर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए| उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कंद-मूल खाने पड़े, जमीन पर सोना पड़ा| 14 साल तक भगवन श्रीराम ने संघर्ष किया, मुश्किलों का सामना किया| लेकिन अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटे, इसीलिए कहते है कि, 'रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई'- ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि, वो दिल्लीवासियों की जिन्दगी बेहतर बनायेंगे, उन्हें सम्मानजनक जीवन देंगे, उनके बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे, उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ देंगे| इस वचन को पूरा करने के लिए अरविन्द केजरीवाल जी ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है| पिछले 9 साल में हमारे विरोधियों ने अरविन्द केजरीवाल जी के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया है, हर काम में अडंगा डाला है, हर पॉलिसी को फेल करने की कोशिश की है| जिस तरह तमाम मुश्किलों के बाद भी भगवान् श्रीराम अपने वचन से पीछे नहीं हटे, उसी तरह पिछले 9 सालों में अरविन्द केजरीवाल जी भी दिल्लीवालों को दिए अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटे है|

108. अरविन्द केजरीवाल जी के इस संघर्ष से दिल्लीवालों की जिन्दगी बदली है| अब महिलाओं को पानी के लिए टैंकरों के आगे लम्बी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अब सड़क, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिल सकी है, जो महिलाएं सालों तक अपने घर की चारदीवारी में बंद थी, वो पिंक टिकट के माध्यम से अब घर से बाहर निकल सकती है, वे बुजुर्ग जो दशकों से तीर्थ-यात्रा पर जाने की कयास लगाये बैठे थे, अब मुख्यमंत्री तीर्थ-यात्रा योजना की बदौलत फ्री तीर्थ-यात्रा कर पा रहे है, वो बुजुर्ग परिवार जिसने सीमा पर अपना बेटा खोया है, उन्हें सम्मान मिला है, गरीब परिवारों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिली है, हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिला है| मुझे गर्व है कि पिछले 9 सालों से तमाम अडचनों के बाद भी अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्लीवासियों से किया अपना वादा निभाया है, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो

109. मैं ये नहीं कहती कि हमनें सब कुछ कर दिया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है लेकिन पिछले 9 सालों में जितना काम हुआ, जितनी मुश्किलों के बावजूद हुआ है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है|

[भाग क]

110. अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि, आने वाले वर्ष में भी राम राज्य को साकार करने का प्रयास जारी रहेगा। इस वर्ष का बजट प्रस्ताव पेश करने के पहले, मैं दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ।

111. वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी की GSDP में 9.17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है - जो पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख 15 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर, इस साल 11 लाख 8 हजार करोड़ रुपये हो जाना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली का GSDP वर्तमान क़ीमतों पर 15.13 प्रतिशत और स्थिर क़ीमतों पर 7.85 प्रतिशत बढ़ा है।

112. दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का 1.55% है| लेकिन दिल्ली का राष्ट्रीय GDP में योगदान इससे दोगुने से भी ज्यादा है| 2023-24 मे दिल्ली का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान स्थिर क़ीमतों पर 3.89 प्रतिशत होने जा रहा है।

संशोधित अनुमान 2023-24

113. अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित बजट का अनुमान 74 हजार 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह संख्या 2022-23 में व्यय की गई 64 हजार 110 करोड़ रुपये से 16.83 प्रतिशत अधिक है। 74 हजार 900 करोड़ रुपये के प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान में 56 हजार 440 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए और 18 हजार 460 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के तहत है। वर्ष 2023-24 में स्थापना एवं अन्य अपरिहार्य व्यय 35 हजार 100 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 35 हजार 275 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए पूरक अनुदान मांगें

114. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान में 824.86 करोड़ रूपये की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी| इसलिए मैं पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन से अनुरोध करती हूं।

115. और अब, मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान पेश करती हूं।

<u>बजट अनुमान 2024-25</u>

116. वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट का अनुमान 74 हजार 900 करोड़ रूपये था| वित्त वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान बढ़कर 76 हजार करोड़ रुपये है| बजट अनुमान में 60 हजार 911 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 15 हजार 89 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है।

117. अध्यक्ष महोदय, जैसा की हम सब जानते है कि केंद्र सरकार ने हमेशा दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। केंद्र सरकार 'कर और शुल्क' के केंद्रीय पूल से सभी राज्यों को उनका हिस्सा देती आई है, मगर दिल्ली को उसके हक़ का हिस्सा कभी नहीं मिला। जहां, अन्य राज्यों को केंद्र सरकार से सभी करों का 41 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। वहीं, केंद्रीय पूल से दिल्ली का हिस्सा वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक केवल 325 करोड़ रुपये बना रहा और 2023-24 से वो भी Zero हो गया है। अगर केंद्र सरकार ये सौतेला व्यवहार न करें और दिल्ली को बजट में उसका उचित हिस्सा दे, तो ये रकम हर वर्ष 7 हजार 200 करोड़ रूपये से भी ज्यादा होगी| लेकिन केंद्र सरकार के इस सौतेले व्यवहार के बावजूद भी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के बजट में पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है।

118. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित 76 हजार करोड़ रुपये के कुल व्यय में:

- 58 हजार 750 करोड़ रुपये कर राजस्व से,
- 1 हजार करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से,
- 10 हजार करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से,
- 379 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियों से,
- जीएसटी प्रतिपूर्ति (compensation) से शून्य, 3 हजार 223.94 करोड़ रुपये केंद्रीय योजनाओं से
- और केवल 1 हजार 168 करोड़ रुपये भारत सरकार के सहायता अनुदान के रूप में है और बाकी राशि आरंभिक शेष से पूरा किया जाना है।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

119. अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक वहां की लोकल बॉडी सशक्त न हो। इसे देखते हुए हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वर्ष 2024-25 के बजट में कुल 8 हजार 423 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसमें से 3 हजार 153 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ़-सफाई के लिए है| और 2 हजार 955 करोड़ रुपये बुनियादी कर दायित्व (BTA) और 2 हजार 315 करोड़ रुपये स्टैंप और पंजीकरण शुल्क तथा पार्किंग शुल्क के रूप में दिया जाएगा।

शिक्षा

120. केजरीवाल सरकार लगातार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को देती आई है| और साल दर साल ये बढ़ता आया है| इस साल भी मुझे ये बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को आवंटित किया जा रहा है|

121. वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग को प्राथमिकता देते हुए, हमनें इस साल SCERT के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है|

122. नए स्कूल व क्लासरूम्स बनाने के लिए हमनें 190 करोड़ रूपये और मौजूदा क्लासरूम के मेंटेनेंस के लिए 45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है|

123. स्कूल ऑफ़ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली का गौरव है; और आने वाले समय में सभी जोन में इसके विस्तार की योजना है| SoSEs के लिए इस वर्ष 42 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान रखा है| दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है| दिल्ली में कई बार ख़राब मौसम के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है| स्कूलों के बंद होने के बाद भी बच्चों की शिक्षा न रुके इसके लिए दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एक शानदार उपाय के रूप में सामने आया है| इसके नए स्टूडियो, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है|

124. अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार संविधान के 72वें और 73वें संशोधन ने पंचायतों और लोकल बॉडी के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के करीब पहुंचा दिया| ठीक उसी तरह Right to Education Act ने SMC के द्वारा स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के हाथों में स्कूल से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति दी है| स्कूल को छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या अधिकारीयों के

सामने हाथ फ़ैलाने न पड़े इसलिए, इस साल हमारी सरकार ने दिल्ली शिक्षा क्रांति के स्तंभ SMCs के लिए 40 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है|

125. दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंत्रप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, और इसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट बिज़नेस ब्लास्टर्स ने 2 सालों में दिल्ली में युवा एंत्रप्रेन्योर्स की फ़ौज खड़ी कर दी है| इसके लिए, बजट अनुमान 2024-25 में entrepreneurship development program के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

126. Chief Minister Super Talented Coaching Scheme सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जेईई (मेन/एडवांस) एवं नीट परीक्षाओं की तैयारी में मदद करती है, जिसके तहत 600 विद्यार्थियों को वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

127. अध्यक्ष महोदय, खेल भी पढ़ाई जितना महत्वपूर्ण है| दिल्ली में हमारे खिलाडियों को बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएँ मिल सके इसलिए इस वित्त वर्ष में हमनें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 118 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है|

128. इस साल उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए हमनें 1212 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है| दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के लिए 165 करोड़ रूपये, नेताजी सुभाष टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के लिए 56 करोड़ रूपये, दिल्ली फर्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़,दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 41 करोड़, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 92 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया है| साथ ही हमनें अपनी ITIs के लिए 242 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है|

129. महोदय, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में एंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार अपने यूनिवर्सिटीज और ITIs में "बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर" के नाम से एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

130. मुझे इस सदन को बताते हुए ख़ुशी है कि, इस साल हम शिक्षा के क्षेत्र में 16 हजार 396 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित कर रहे है|

स्वास्थ्य सेवाएं

131. अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों में अच्छी सुविधा बनी रहे, हमारे अस्पताल वर्ल्ड क्लास बने रहे इसलिए लिए इस वित्त वर्ष में, अस्पतालों के लिए 6 हजार 215 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है| इस वित्त वर्ष में एल.एन.जे.पी अस्पताल के लिए 719 करोड़ रूपये, गुरु तेगबहादुर अस्पताल के लिए 497 करोड़ रूपये, जीबी पन्त अस्पताल के लिए 490 करोड़ रूपये, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए 352 करोड़ रूपये, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रूपये, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के लिए 291 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है|

132. अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला क्लीनिक के अपने शानदार मॉडल के जरिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए इलाज को सुगम बना दिया है| दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के जरिए शानदार इलाज मिलता रहे इस दिशा में इस साल 212 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है|

133. दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरुरी दवाइयों की कमी न हो और हर जरूरतमंद को समय पर निशुल्क दवाइयां मिल सके इसलिए इस वित्त वर्ष में 658 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है|

134. इस वित्त वर्ष में नये अस्पतालों के निर्माण और रि-मॉडलिंग के तहत मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

135. केजरीवाल सरकार के दिल्ली आरोग्य कोश के अंतर्गत - मुफ्त इलाज, सर्जरी, रेडियोलॉजी, diagnostic सेवाएं और चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जा रही है। इस साल दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा फ्री उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है|

136. दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) की नई एम्बुलेंस ख़रीदने के लिए मैं बजट में 194 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूँ।

137. महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8 हजार 685 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करती हूँ||

उर्जा

138. अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में 58 लाख 86 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 68.33 प्रतिशत यानी कि 40 लाख 22 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को केजरीवाल सरकार की सब्सिडी का

लाभ मिल रहा है, साल 2023 में दिल्ली में 3 करोड़ 41 लाख बिजली के बिल जीरो आए| केजरीवाल सरकार ये सब्सिडी इस साल भी जारी रखेगी|

139. दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने "दिल्ली सोलर पॉलिसी -2023" तैयार की है, जो अभी गजट नोटीफीकेशन की प्रक्रिया में है और जल्द लागू होगी| जो भी उपभोक्ता 400 से अधिक यूनिट बिजली इस्तेमाल करते है, सोलर पैनल लगाने के बाद उनका बिजली का बिल भी जीरो आने लगेगा| सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी तो देगी ही साथ ही सोलर पैनल से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए भी पैसे देगी।

140. महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए मैं विद्युत क्षेत्र के लिए 3 हजार 353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करती हूं।

जलापूर्ति एवं सीवर

141. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के हर घर को पानी और सीवर सुविधा का अधिकार मिले, इस दिशा में मैं दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7 हजार 195 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करती हूँ।

परिवहन

142. आज दिल्ली में 7582 बसों की फ्लीट मौजूद है, जिनसे रोजाना 41 लाख से अधिक यात्री सफ़र करते है| इसे और बढ़ाने की दिशा में, 1,900 नई ई-बसों के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इस साल में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है| डीटीसी और क्लस्टर बसों में 'पिंक टिकट' के जरिए महिलाओं को फ़्री बस यात्रा की स्कीम जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

143. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के प्रयासों से दिल्ली मेट्रों के फेज 4 का रास्ता साफ हो चुका है| इसके तहत जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम कॉरिडोर, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन कॉरिडोर, मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर के कुल तीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए एमओयू को मंज़ूरी दी गई है| 65.2 किलोमीटर के इन तीनों मेट्रो कॉरिडोर पर 45 स्टेशन होंगे| इस वित्त वर्ष में, दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है|

144. दिल्ली की तरक़्क़ी की आधारशिला - केजरीवाल सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की दिशा में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 5,702 करोड़ रुपये का बजट को प्रस्तावित करती हूँ|

विधि एवं न्याय

145. महोदय, केजरीवाल सरकार दिल्ली में शानदार न्यायिक इंफ्रास्ट्रकर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमनें 4 नए कोर्ट कॉप्लेक्स बनवाने को मंजूरी दी है| जिनकी कुल लागत 1 हजार 108 करोड़ रुपये है। सरकार ने बड़े स्तर पर जजों की नियुक्तियों पर भी काम किया है|

146. जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना का भी प्रस्ताव है, और इस योजना के लिए 2024-25 के बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

147. मैं, विधि एवं न्याय विभाग व न्यायालयों के विभिन्न कार्यों के लिए 2024-25 के बजट में 3 हजार 98 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूं।

सड़क एवं अन्य आधारभूत ढांचा

148. अध्यक्ष महोदय, दुनिया के किसी भी राज्य में, सड़कों की गुणवत्ता से इकॉनमी की रफ़्तार तय होती है। जितना ज़्यादा सरकार सड़कों पर खर्च करती है, उतना ही ज़्यादा आम आदमी के लिए समय और पैसों की बचत मुमकिन होती है।

149. इस दिशा में वर्तमान में दिल्ली में कई फ़्लाइओवर और एलिवेटेड कोरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है, जो वर्ष 2024-25 में दिल्ली वालों को समर्पित किए जायेंगे| जैसे:

- बारापुला फेज-III,
- करावल नगर- घोंडा-बृजपुरी जंक्शन पर मेट्रो के साथ डबल डेकर फ्लाईओवर
- 'नंद नगरी से गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर ',
- रानी झांसी रोड जंक्शन से आजादपुर कोरिडोर पर मेट्रो के साथ डबल डेकर फ्लाईओवर
- आनंद विहार आरओबी से अप्सरा बॉर्डर आरओबी तक का फ़्लाइओवर
- मुकरबा चौक, आउटर रिंग रोड पर अंडरपास

150. पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का काम भी क़रीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मुझे ये बताते हुए ख़ुशी है कि, 2024-25 के अंत तक दिल्ली में 6 नए फ्लाईओवर दिल्लीवालों को समर्पित किए जायेंगे|

151. दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाकर, दुनिया की सबसे शानदार रोड नेटवर्क में शामिल करने के मिशन के तहत, दिल्ली में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 1 हजार 768 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूं।

शहरी विकास

152. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के जीवन में सुधार लाने को, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कें और नालियों के विस्तार का काम युद्ध स्तर पर जारी रखने के लिए, बजट अनुमान 2024-25 में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

153. महोदय, सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'Strengthening and augmentation of infrastructure scheme' जिसे MLALAD के नाम से जाना जाता है| इसके तहत सड़क, गलियां, स्ट्रीट लाईट इत्यादि को दुरुस्त किया जा रहा है। इस योजना के तहत साल 2023-24 के लिए 1,002 नई प्रॉजेक्ट्स मंजूर किए गए, जिनमें से 717 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। विकास कार्यों को जारी रखने के क्रम में, बजट 2024-25 में MLALAD स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

154. अध्यक्ष महोदय, 'मुख्यमंत्री सड़क पुनःनिर्माण योजना' और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत दिल्ली की सड़कों और गलियों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और Dark spots घटाकर सड़कों को सुरक्षित बनाया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में इस योजना के तहत सड़कों और स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान करती है।

155. अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास और शहरी विकास की योजनाओं के लिए 9 हजार 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूं।

गांवों का विकास

156. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गाँवों की जनता ने अरविन्द केजरीवाल जी को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। गांवो को तरक्की की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस साल केजरीवाल सरकार

दिल्ली के 360 से अधिक गांवों मे लगभग 1000 किलोमीटर सड़कें बिछाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा।दिल्ली के गांवों के विकास के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ का बजट प्रस्तावित करती हूँ|

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

157. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों को मासिक पेन्शन देने का काम कर रही है। केजरीवाल सरकार द्वारा, लगभग 9 लाख 3 हजार जरूरतमंदों को हर महीने 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 3 लाख 75 हजार विधवा एवं संकटग्रस्त महिलाएं (women in distress) और 1 लाख 23 हजार दिव्यांगजन शामिल हैं। इन लाभार्थियों के लिए 2024-25 के बजट में 2,714 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

158. 2024-25 से महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केजरीवाल सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है| इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी। इस क्रांतिकारी योजना के तहत, 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति महीना 1000 रूपये की राशि मिलेगी। निम्नलिखित महिलायें इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगी -

1. जो अभी सरकार की किसी पेन्शन स्कीम का हिस्सा हो,
2. स्वयं सरकारी कर्मचारी हो या
3. Income tax payer हो

159. स्कीम के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि, वो किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर उस महिला को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर्म के साथ, हर महिला को अपने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के लिए 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

160. महोदय, सामाजिक उत्थान और महिला सशक्तिकरण को समर्पित केजरीवाल सरकार की इन सभी योजनाओं के लिए, मैं समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC/ST/OBC कल्याण विभाग के लिए 6,216 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूं।

[भाग ख]

161. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट भाषण के पहले भाग में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। अब मैं सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा करूंगी।

162. वर्ष 2023-24 में जनवरी, 2024 तक GST और VAT के लिए टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष (जनवरी 2023 तक) की तुलना में 13.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 हजार 445 करोड़ रुपये रहा।

163. अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 सालों से हमेशा व्यापारियों और व्यापार की बेहतरी के लिए काम किया है| ईमानदार आदमी परेशान न हो और सरकार का राजस्व बढ़ता रहे| इस दिशा में हमनें व्यापारियों के लिए नियमों को आसान बनाया है, अब सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बिना फेसलेस तरीके से व्यापारी घर बैठे अपने सभी काम करवा सकते है| इसी का नतीजा है कि पिछले सालों में दिल्ली में व्यापार और टैक्स कलेक्शन दोनों में वृद्धि हुई है|

164. आज दिल्ली में कुल 7.88 लाख GST करदाता हैं, जिसमें से दिल्ली सरकार के अधीन 4.82 लाख करदाता आते हैं। बाक़ी 3.06 लाख करदाता केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं।

165. अध्यक्ष महोदय, हमनें दिल्ली में ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है| ग्राउंड इंटेलिजेन्स, Business Intelligence and Fraud Analysis (BIFA), GST Portal की इंटेलिजेंस को आधार बनाते हुए, दिल्ली सरकार special auditing कर रही है - ताकि टैक्स चोरी रुक सके। auditing process के ज़रिए, इस साल में 167 स्पेशल audits करके, इस वर्ष कुल 5 हजार 321 करोड़ का Tax Deficiency पकड़ा है। इसी ग्राउंड इंटेलिजेन्स के दम पर, फ़र्ज़ी व्यापारियों के ख़िलाफ़ भी केजरीवाल सरकार सख़्ती से ऐक्शन लेते हुए आयी है। Intelligence reports के मुताबिक़ फ़ील्ड verification करके, हमने कुल 2911 Fake Firms को suspend किया गया है, और 1316 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है।

166. अब केजरीवाल सरकार का अगला कदम जीएसटी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक और पूरी GST Tax Administration को फेसलेस बनाना है| इस दिशा में हमारी सरकार IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एक डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है| ये आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और डेटा-एनालिटिक्स के जरिए रिटर्न्स ट्रैक करने, मोनिटरिंग करने,

रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा| इससे फाइलों की प्रोसेसिंग टाइम और गलतियाँ कम होगी| इससे डिफाल्टरों और टैक्स चोरी का पता लगाने और उनपर एक्शन लेने में सहायता मिलेगी| ये पूरी प्रक्रिया सिस्टम में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी साथ ही फेसलेस होने के कारण Tax Administration के भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगी||

167. दिल्ली सरकार आबकारी राजस्व में वृद्धि और प्रभावी तरीक़े से उत्पाद विनयमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार Faceless Enforcement और Excise Intelligence Bureau को मज़बूत करने जैसे उपायों के ज़रिये Liquor के अवैध कारोबार से मुक्ति सुनिश्चित करने और शहर में Liquor का quality control सुनिश्चित करने के लिए वचनवद्ध है।

168. सरकार ने सितंबर 2022 से उत्पाद शुल्क आधारित व्यवस्था बहाल कर दी है। Hospitality उद्योग रोज़गार मुहैया कराने, टैक्स जनरेशन और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार Liquor Supply System Management की मौजूदा तकनीक को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है।

169. वर्ष 2023-24 में (जनवरी, 2024 तक) वाहन टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष (जनवरी 2023 तक) की तुलना में 11.88 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2 हजार 687.98 करोड़ रुपये रहा।

170. वर्ष 2023-24 में (जनवरी, 2024 तक) स्टांप और पंजीकरण शुल्क (भू- राजस्व सहित) का टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष (जनवरी 2023 तक) की तुलना में 16.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5 हज़ार 797 करोड़ रूपये रहा।

171. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी को सलाम करती हूँ| जिस जिम्मेदारी और लगाव के साथ एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, ठीक उसी जिम्मेदारी के साथ अरविन्द केजरीवाल जी ने - दिल्ली में 2 करोड़ लोगों के अपने परिवार के लिए - सरकार को चलाया है| उन्होंने दिल्ली के हर इंसान का ख्याल रखा है, चाहे एक पिता की तरह बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो या बेटा बनकर बुज़ुर्ग माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना हो, चाहे वो बहन के हाथ में हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देनी हो या भाई का इलाज करवाना हो - इस दस साल के सफ़र में अरविन्द केजरीवाल जी ने ये सभी ज़िम्मेदारियाँ दिल्ली में अपने 2 करोड़ लोगों के परिवार के लिए निभाई है| मुझे विश्वास है कि दिल्ली वाले अपने बेटे अरविन्द केजरीवाल जी के राम राज्य को साकार करने के इस संकल्प में, उन पर सदैव अपना

आशीर्वाद और प्यार बनाए रखेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली वालों के इस प्यार के साथ, अगले 5 साल भी, केजरीवाल सरकार ही इस विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेगी|

जय हिंद, जय भारत।